Shri Kmararkar: I have not got the figures for those days, but I have got figures for the whole years, 1952 and 1954. In 1952, we imported 1.51 million bales and in 1954-55 1.21 million bales.

Shri B. K. Das: May I know whether that quality of jute that is available in India has also been imported from Pakistan, what is the reason for the preference?

Shri Karmarkar: The fact is: it is not about the quality but about the quantity required. We anticipate that at the present moment our short fall will be about 1.2 million bales in addition to what we grow. We require this additional quantity and that is why the import is made.

Shri N. B. Chowdhury: May I know whether the Government have entered into any agreement with the Pakistan Government regarding the total quantity of raw jute that the Government wants to import from that country during these years and, if so, what is that quantity?

The Minister of Commerce and Industry and Iron and Steel (Shri T. T. Krishnamachari): Any such agreement that we have had in the past, which you may take as being current, is only in regard to licence for import and not actually to import.

Shri N. B. Chowdhury: What is the total quantity that the Government want to import from other countries during the current year?

Shri T. T. Krishnamachari: We are not importing any jute from any other country except Pakistan.

U.N.O.

*449. **Shri Kasliwal:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the work of the U.N. Committee on Information from Non-Self-Government territories was proposed to be broadened; and

(b) if so, whether any of the colonial powers gave notice thereupon that they would withdraw from the Committee if such a proposal was accepted?

The Deputy Minister for External Affairs (Shri Anil K. Chanda): (a) Yes. During the discussion of the Report of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories in the Fourth Committee of the General Assembly, the delegations of Burma, Liberia, Saudi Arabia, Syria and Thailand submitted a joint amendment which sought to extend the powers of the Committee. Subsequently the sponsors withdrew the amendment and the Fourth Committee adopted a resolution extending the life of that Committee on the same terms of reference as before for a further period of three years.

(b) Yes. The Administering Powers opposed this amendment and the representative of the United Kingdom declared that if the joint amendment was adopted by the Fourth Committee, this country would not take part in the work of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories in future.

Shri Kasliwal: May I know whether, after the amendment by these four sponsoring powers had been withdrawn, this item is no longer on the agenda of the U.N. Committee on Information?

Shri Anil K. Chanda: I do not understand the question. The Committee has accepted the resolution and had dropped the amendment.

भाखड़ा नंगल परियोजना

*४५०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नंगल परियोजना से बिजली उत्पन्न करने का अन्तिम लक्ष्य कब तक पूरा हो जायगा; और

(ख) १९५५ के लिए निर्धारित लक्ष्य में से कितनी बिजली उत्पादित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) २४२४ हजार किलोवाट बिजली पैदा करने वाली दो मशीनों के अतिरिक्त जो इस समय चालू हैं, ९०९० हजार किलोवाट को पांच मशीनों के और २४२४ हजार किलोवाट की चार मशीनों के १९५९-६० तक चालू होने की संभावना है। बिजली की मांग बढ़ जाने पर जब कभी भी आवश्यकता होगी ९०९० हजार किलोवाट की चार मशीनें भी जोड़ दी जायेंगी।

(ख) अधिष्ठापित धारिता (इन्स्टाल्ड केपेसिटी) और निर्धारित लक्ष्य दोनों ४८,००० किलोवाट हैं। जनवरी १९५५ के आरम्भ से नवम्बर १९५५ के अन्त तक ११,७०,३०,००० के० डब्लू० एच० बिजली पैदा की गई।

श्री के० सी० सोधिया : देहातों को इलेक्टिफाई करने के लिये भी कुछ बिजली दी जाती है या नहीं ?

श्री हाथी : जी हां, जरूर दी जायगी ।

श्री के० सी० सोधिया : कितनी खर्च हो रही है ?

श्री हाथी : अभी तक तो एक पावर हाउस चल रहा है । उसमें से दस हजार किलोवाट तो दिल्ली को दी जाती है और कुछ भाखड़ा प्रोजेक्ट में उपयोग होती है और कुछ पंजाब में उपयोग होती है ।

श्री के० सी० सोधिया : देहाती क्षेत्र में कितनी बिजली खर्च हो रही है ? क्या देहाती क्षेत्र में भी कुछ बिजली दी जाती है ?

श्री हाथी : अभी तक तो नहीं दी जाती है ।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि भाखड़ा बांध पर कितना खर्च हुआ है और काम किस तरह से चल रहा है ?

Mr. Deputy-Speaker : This relates to electric power.

श्री हाथी : इलेक्ट्रिसिटी पर ३३ करोड़ ।

श्री बंसीलाल : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान में कितनी बिजली दी जाती है ?

श्री हाथी : राजस्थान को अभी बिजली नहीं दी जाती । जब दूसरा पावर हाउस बन जायगा तब राजस्थान को बिजली दी जायेगी ।

श्री बंसीलाल : राजस्थान को कब तक बिजली मिल जायगी ।

श्री हाथी : १९५९–६० तक ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

*४५१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन निश्चित लक्ष्य में से अब तक कितने विकास खंड आरम्भ किये गये हैं; और

(ख) उन विकास खंडों के अधीन कितने गांव कार्यक्रम के अन्दर आ गये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) १२०० में से १०३१ ब्लाक ।

(ख) लगभग १,०६,०५७ गांव ।

श्री भागवत झा आजाद : प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्ति काल तक सम्पूर्ण देश के ग्रामों का कौन सा प्रतिशत इन विकास खंडों के अन्तर्गत आ जायेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : इसका लक्ष्य यह रखा गया है कि मुल्क का चौथाई हिस्सा इसके अन्दर आ जायेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या आप बतला सकते हैं कि जन सहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत ग्रामों द्वारा जो सहायता दी गयी है क्या उसका रुपयों में मूल्यांकन आपके पास है ?

श्री एस० एन० मिश्र : श्रम साधन या और तरह से जो जन सहयोग प्राप्त हुआ है अगर उसकी क़ीमत लगायी जाये तो १५.२ करोड़ रुपये के क़रीब होगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि जो विकास खंड खोले जाते हैं उनकी मियाद केवल तीन वर्ष होती है, जब कि व्यावहारिक अनुभव यह बतलाता है कि पहला एक वर्ष केवल तैयारी में ही बीत जाता है । इसलिये क्या गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि तीन वर्ष के बदले कम से कम पांच वर्ष तक उनको एक ही क्षेत्र में चलता रहने दिया जाय ?

श्री एस० एन० मिश्र : जहां तक राष्ट्रीय विस्तार सेवाखंडों का सवाल है उनकी मियाद तो तीन साल की ही है, लेकिन सामुदायिक योजना खंडों के बारे में तीन साल से बढ़ा कर चार साल की मियाद कर दी गयी है । माननीय